उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 24 16-31 दिसंबर 2025 ₹ 20/-

आर.एस.एस. के शीर्ष नेतृत्व के बयान पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

- असम में बांग्लादेश से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़
- बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता की हत्या से तनाव
- सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बढ़ता टकराव
- इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने पर विवाद

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

आर.एस.एस. के शीर्ष नेतृत्व के बयान पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया 04
असम में बांग्लादेश से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ 09
प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा उर्दू मीडिया की नजर में 11
अजमेर दरगाह में प्रधानमंत्री द्वारा पेश की गई चादर 13
पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की नई पार्टी 15

विश्व

बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता की हत्या से तनाव 16
पाकिस्तान से रक्षा समझौते के बाद लीबिया के सेना प्रमुख की मौत 19
इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा 20
पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट के हमलों में वृद्धि 22
डेनमार्क के शिक्षण संस्थानों में बुर्का पर प्रतिबंध का फैसला 23

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बढ़ता टकराव 24
इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने पर विवाद 26
इजरायल द्वारा ईरान पर दोबारा हमले की चेतावनी 30
आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी हमले 31
पाकिस्तान के सेना प्रमुख को सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान 32

सारांश

उर्दू मीडिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उर्दू अखबारों ने संघ प्रमुख द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र करार देने की आलोचना की है। इन अखबारों का यह भी आरोप है कि मोहन भागवत ने सिर्फ हिंदुओं से संगठित होने की अपील की है ताकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का निराकरण किया जा सके। उर्दू मीडिया का कहना है कि मोहन भागवत का यह बयान भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भारतीय सांविधान किसी विशेष धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है।

इसके अतिरिक्त हाल ही में दत्तात्रेय होसबोले ने मुसलमानों से अपील की थी कि वे पर्यावरण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सूर्य, नदियों और वृक्षों की पूजा करें। उन्होंने मुसलमानों से सूर्य नमस्कार को अपनाने की भी अपील की। इस पर जमीयत उलेमा के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि दत्तात्रेय होसबोले जैसे शिक्षित व्यक्ति को भी इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मुसलमान 'तौहीद' (एकमात्र अल्लाह) में आस्था रखते हैं। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना करता है या उसके आगे सिर झुकाता है तो यह इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है और ऐसे व्यक्ति को इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है।

भारत और बांग्लादेश के संबंधों में दिन-प्रतिदिन कटुता आती जा रही है। पिछले दिनों कुछ नकाबपोश हमलावरों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हादी को भारत विरोधी माना जाता था। हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी अभियान चलाया गया और वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया। यह सिलसिला अभी भी जारी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने मीडिया समूहों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बांग्लादेश के दो बड़े अखबारों के कार्यालयों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय है। वह बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक देश बनाने और देश के सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ करने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं को तैयार कर रही है। इसमें बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आईएसआई बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों के सहयोग से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने की तैयारी कर रही है। हाल ही में असम और त्रिपुरा में बांग्लादेश के एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन के जुड़े 11 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर पूर्वोत्तर भारत में जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की साजिश रच रहा है।

विश्व की मुस्लिम राजनीति एक नया मोड़ ले रही है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात समर्थित दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (एसटीसी) ने यमन के कुछ शहरों व तेल के भंडारों पर फिर से कब्जा कर लिया है। इस पर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में ठन गई है। संयुक्त अरब अमीरात से यमन में हथियारों की खेप आने के बाद सऊदी अरब ने यमन के एक बंदरगाह पर बमबारी की है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों में कई अन्य मामलों को लेकर भी गंभीर मतभेद हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को हो रही है। पिछले दिनों उसने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगर सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान से सैन्य सहयोग मांगता है तो वह इनकार नहीं कर सकता। इससे पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में कटुता आएगी। पाकिस्तान को डर है कि ऐसी स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात लगभग 20 लाख पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश से निष्कासित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी।

आर.एस.एस. के शीर्ष नेतृत्व के बयान पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

हिंदुस्तान (23 दिसंबर) के अनुसार कोलकाता में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बांग्लादेश के घटनाक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने दुनियाभर के हिंदुओं से भी अपील की है कि वे बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार हिंदुओं की मदद करें। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। मोहन भागवत ने कहा कि हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। भारत सरकार को भी इस संबंध में कुछ करना होगा। हो सकता है कि वह पहले से ही कुछ कर रही हो। कुछ बातें सार्वजनिक हैं तो कुछ नहीं। कभी उसके परिणाम निकलते हैं तो कभी नहीं, लेकिन कुछ तो करना होगा। पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए भागवत ने कहा कि बंगाल में इस्लामिक कट्टरपंथ तेजी से बढ़ रहा हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों में वृद्धि हुई है। बांग्लादेश के हालात और मुसलमानों की घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल में स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है।

कौमी तंजीम (22 दिसंबर) के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है। बाबरी मस्जिद का निर्माण का फैसला वोट बटोरने के लिए किया गया है। इससे न तो हिंदुओं को कोई लाभ होगा और न ही मुसलमानों को। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है। जब मोहन भागवत से पूछा गया कि क्या किसी धार्मिक स्थल के निर्माण में सरकारी धन का इस्तेमाल किया जाना उचित है? इस पर उन्होंने कहा कि सरकार को कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बनाना चाहिए। जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था तब सरदार वल्लभभाई पटेल गृह मंत्री थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने

नहीं है कि हम किसी पर हमला करने का इरादा रखते हैं।

मोहन भागवत से पूछा गया कि सेक्युलरिज्म के दायरे में रहते हुए हिंदुओं की सुरक्षा कैसे की जा सकती है और हिंदुत्व के आधार पर युवाओं का निर्माण कैसे किया जा सकता है? इस पर भागवत ने कहा कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। देश कानून से चलता है, धर्म से नहीं। भागवत ने हिंदुत्व को कर्मकांडों से अलग करते हुए कहा कि सिर्फ मंदिर जाना ही हिंदू होने की पहचान नहीं है, बल्कि व्यक्ति का आचरण, नैतिकता और समाज के प्रति उसका व्यवहार ही उसका वास्तविक धर्म है। उन्होंने साफ किया कि सेक्युलरिज्म कोई पश्चिमी अवधारणा नहीं है जिसे हम पर जबरदस्ती थोपा गया हो, बल्कि यह शासन चलाने की एक व्यवस्था है। सेक्युलरिज्म सरकार की एक नीति है। राज्य चलाने वाली व्यवस्था सेक्युलर रही है और राज्य सेक्युलर ही रहेगा।

मंदिर के उद्‌घाटन समारोह में भाग लिया था, लेकिन इसके निर्माण में सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया। सरकार को एक ट्रस्ट बनाने के लिए कहा गया था और उसने ऐसा किया, लेकिन सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए कोई धनराशि नहीं दी। हमने जनता के सहयोग से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया।

मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है। हमें नहीं पता कि यह कब से उगता है, तो क्या इसके लिए भी संवैधानिक मंजूरी की जरूरत है? जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है व भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है वह हिंदू है और हिंदू प्रभाव में है। यही संघ का दृष्टिकोण है। अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करती है तो वह ऐसा करे या न करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि हम हिंदू हैं और भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि कई लोग आरएसएस को भाजपा के नजरिए से देखते हैं। आप इसे देखकर नहीं समझ सकते। आपको इसे महसूस करना होगा। भागवत ने कहा कि प्रशिक्षण और अभ्यास का अर्थ यह

औरंगाबाद टाइम्स (22 दिसंबर) के अनुसार आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत के मुसलमानों को नदियों, वृक्षों और सूर्य की पूजा जैसी परंपराएं अपनानी चाहिए। इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उन्होंने हिंदू परंपराओं पर आपत्ति जताने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मुस्लिम भाई भी सूर्य नमस्कार करें तो उन्हें इससे क्या नुकसान होगा? इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मस्जिद जाने से रोका जाएगा। हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। यह सबके लिए बात करता है। होसबोले ने कहा कि सूर्य नमस्कार का संबंध धर्म से नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पर आधारित है। अगर नमाज पढ़ने वाले लोग भी नमस्कार करते हैं तो क्या यह गलत

उनकी उपासना पद्धति किसी भी समझदार व्यक्ति से छिपी हुई नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा कि अफसोस की बात है कि होसबोले जैसे शिक्षित व्यक्ति को भी इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 'तौहीद' और 'रिसालत' (अल्लाह का संदेश वाहक) इस्लाम के मूल स्तंभ हैं। इन दोनों को नहीं मानने वाले को इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। इस देश की मिट्टी व प्रकृति से प्रेम करना और उसकी रक्षा करना पूजा करने से बिल्कुल अलग है। तौहीद पर विश्वास रखने वाले भारतीय मुसलमानों को वृक्ष, धरती, सूर्य, समुद्र या नदी की पूजा करने की सलाह देना इस बात का प्रमाण है कि संघ 'प्रिय' और 'पूज्य' के बीच के बुनियादी अंतर को समझने और समझाने में विफल रहा है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि संघ वैचारिक और व्यावहारिक रूप से देश का मार्गदर्शन करने की योग्यता नहीं रखता।

है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको नमाज छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रकृति पूजा से जुड़ी परंपराएं भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। ये परंपराएं सभी नागरिकों के लिए फायदेमंद हैं। अगर मुसलमान भी पर्यावरण के नजरिए से नदियों या वृक्षों की पूजा करते हैं तो इसमें गलत क्या है? आरएसएस किसी भी समुदाय को अपना दुश्मन नहीं मानता। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि वे समाज और राष्ट्र के कल्याण के कार्यक्रमों में भाग लें। लोगों को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे हिसाब से मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारत विभाजन का उल्लेख करते हुए होसबोले ने कहा कि हर कोई जानता है कि उस दौरान हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। हिंदू दर्शन सभी जीवों और प्रकृति के प्रति अहिंसा की शिक्षा देता है।

अवधनामा (24 दिसंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि होसबोले ने मुसलमानों को सूर्य, नदियों और वृक्षों की पूजा करने की सलाह दी थी। मदनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इस देश में सदियों से साथ रहते आए हैं। मुसलमान 'तौहीद' (एक अल्लाह) में आस्था रखते हैं और

मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा ने सद्भावना, संवाद और आपसी सम्मान के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। हमने आगे बढ़कर संघ और अन्य हिंदूवादी संगठनों के मन में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की है। इसी क्रम में संघ के तत्कालीन सरसंघचलाक के.एस. सुदर्शन से भी हमारी लंबी बातचीत हुई थी। जमीयत उलेमा आज भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमें खेद है कि इस सद्भावनापूर्ण पहल का सकारात्मक उत्तर देने के बजाय संघ के कुछ पदाधिकारी मुसलमानों और इस्लाम के प्रति आक्रामक और उत्तेजनात्मक रवैया अपना रहे हैं। यहां तक कि वे अपनी पूजा पद्धति को मुसलमानों पर लादने की कोशिश कर रहे है। यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।

महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा का यह स्पष्ट और सैद्धांतिक मत है कि भारत में राष्ट्र की आधारशिला देश है। इस देश में रहने वाले सभी नागरिक एक राष्ट्र हैं, चाहे उनका धर्म या विचारधारा कुछ भी हो। हमारे दृष्टिकोण में राष्ट्रत्व का संबंध भूमि से है। जबकि आरएसएस राष्ट्र की अवधारणा को हिंदू समुदाय और एक विशेष सांस्कृतिक सोच पर आधारित करना चाहता है।

उर्दू टाइम्स (29 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा आरएसएस की राजनीतिक शाखा है। आज संघ के स्वयंसेवक ही भाजपा और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आरएसएस स्वयं को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन भाजपा की सारी नीतियां वही तय करता है। मोहन भागवत का यह कहना कि आरएसएस का उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना नहीं है, हकीकत से कोसों दूर हैं। हकीकत यह है कि आरएसएस भले ही सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करे, लेकिन उसका लक्ष्य राजनीतिक है। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आरएसएस सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन है तो हिंदू राष्ट्र पर बहस में उसके शामिल होने का क्या मतलब है? आरएसएस राजनीतिक बयानबाजी करके देश की एकता और सामाजिक सद्भावना को खतरे में डालता है। इसके बावजूद वह दावा करता है कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। संसद में कौन सा विधेयक लाया जाए और देश में किस तरह का कानून लागू किया जाना चाहिए यह सब आरएसएस के मुख्यालय में तय होता है। इसके बाद भी संघ परिवार यह दावा करता है कि उसे किसी भी राजनीतिक पार्टी से न जोड़ा जाए। यह सच्चाई से आंखें मूंद लेने के बराबर है।

समाचारपत्र ने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस और भाजपा एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आरएसएस जो विचार देता है भाजपा उसे पूरे देश में लागू करती है। क्या वंदे मातरम के मुद्दे से लेकर संविधान से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्दों को हटाने की बहस के पीछे आरएसएस का हाथ नहीं था? क्या देश में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में संघ की भूमिका नहीं थी? शारीरिक अभ्यास के नाम पर योग को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया। शिक्षण संस्थानों में गीता पाठ को अनिवार्य किया गया। पौराणिक किस्से और कहानियों को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया। क्या यह सब आरएसएस के इशारे पर नहीं हुआ? क्या पाठ्यपुस्तकों से मुस्लिम शासनकाल को हटाने के पीछे संघ का आदेश नहीं था? ये कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं, जिनका खंडन न तो संघ परिवार कर सकता है और न ही सत्ता में बैठे लोग। इसके बावजूद संघ प्रमुख कहते हैं कि जो लोग आरएसएस और भाजपा को एक दूसरे से जोड़ते हैं, वे गलती करते हैं। संघ प्रमुख के इस

बयान में कितनी सच्चाई है, यह हर भारतीय समझ सकता है।

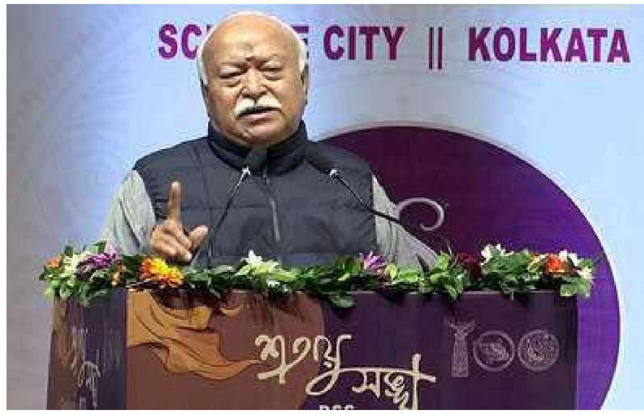

सियासत (24 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में संघ प्रमुख के बयान की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत ने आरएसएस और भाजपा को एक दूसरे के साथ जोड़ने को गलत बताया है। उनका यह बयान एक सोचा-समझा राजनीतिक और सामाजिक संदेश है। मोहन भागवत ने इस धारणा को गलत साबित करने की कोशिश की है कि आरएसएस किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करता है या किसी खास राजनीतिक दल का समर्थन करना उसका मुख्य मकसद है। मोहन भागवत के मुताबिक संघ का एकमात्र लक्ष्य हिंदू समाज की एकता, एकजुटता और भलाई है। हकीकत यह है कि भाजपा का नेतृत्व संघ से जुड़े नेताओं के ही हाथ में रहा है। इसके बावजूद मोहन भागवत का कहना है कि भाजपा और आरएसएस को एक संगठन मानना बिल्कुल गलत है। सवाल यह है कि जब वैचारिक प्रशिक्षण, बौद्धिक दिशा और संगठनात्मक अनुशासन का स्रोत एक ही है तो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ना कैसे गलत है? मोहन भागवत का दावा है कि संघ टकराव वाली सोच के साथ काम नहीं करता। यह निश्चित रूप से एक नैतिक रुख है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में उसकी व्याख्या विवादित रही है।

हिंदुस्तान (28 दिसंबर) ने संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र करार देने की आलोचना की है। समाचारपत्र का कहना है कि संघ प्रमुख ने भारत को हिंदू राष्ट्र करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिए संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख का यह दावा कोई नया नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक जैसा है, इसलिए सभी हिंदू हैं। आरएसएस अपनी स्थापना से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है। अब संघ के शताब्दी वर्ष में यह पेश किया जा रहा है कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र नहीं, बल्कि एक हिंदू राष्ट्र है। संघ प्रमुख के इस बयान से यह सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र का आधार क्या है और वे किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म की जो अवधारणा पेश की गई है, क्या वह हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बरकरार रहेगी? आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है, क्या उसमें देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो सकता है? अगर हिंदुत्व की सोच सभी हिंदुओं को समान दर्जा नहीं देती तो क्या इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह बचेगी?

समाचारपत्र का कहना है कि एक ओर, मोहन भागवत कहते हैं कि देश कानून से चलता है, धर्म से नहीं। दूसरी ओर, वे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं। वे यह भी दावा करते हैं कि सेक्युलरिज्म कोई पश्चिमी अवधारणा नहीं है, जो इस देश पर जबरदस्ती थोपा गया हो। उनकी नजर में सेक्युलरिज्म सरकार की एक नीति है। हालांकि, वे इसके साथ ही हिंदू समाज को संगठित करने पर जोर देते हैं। अगर मोहन भागवत सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं तो उन्हें सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बल्कि सभी भारतीयों को एक करने की चिंता करनी चाहिए। देश के एक विशेष

में जो नफरत और भेदभाव का माहौल बढ़ रहा है वह संघ की संकुचित सोच का ही नतीजा है। देश पर एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति को जबरन थोपा जा रहा है। यह देश की एकता के लिए खतरनाक है।

सवाल यह है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा तो फिर सेक्युलर भारत कहां खो जाएगा? यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि भारत को किसी खास धर्म या समुदाय को सौंपने का फैसला न तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था और न ही देश की स्वतंत्रता के बाद इस बारे में कोई कदम उठाया गया। इसके उलट भारतीय संविधान में सभी धर्मों व नागरिकों को न्याय और बराबरी देने का फैसला किया गया। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि आरएसएस देश की इस पुरानी परंपरा को खत्म करके एक सेक्युलर राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रहा है।

वर्ग को संगठित होने की अपील करके वे यह साबित कर रहे हैं कि हिंदुओं की यह एकता देश की साझी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि यह हिंदुओं की श्रेष्ठता और हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत करने के लिए है ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र में बदला जा सके। संघ के नेताओं के बयान से यह साबित होता है कि हिंदुओं की एकता की बात करने वाले 'अनेकता में एकता' की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। आज देश

असम में बांग्लादेश से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

हमारा समाज (31 दिसंबर) के अनुसार असम और त्रिपुरा में बांग्लादेश के एक आतंकवादी संगठन से जुड़े 11 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। यह इस्लामिक आतंकवादी संगठन हिंसक गतिविधियों के जरिए पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता पैदा करने की तैयारी कर रहा था। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंता ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर असम के बारपेटा, चिरांग, बक्सा और दरांग जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में भी बड़े पैमाने पर खोजी अभियान चलाया गया। इस दौरान 11 इस्लामिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 10 असम के रहने वाले हैं। इनमें से एक आतंकवादी जागीर मियां को त्रिपुरा से गिरफ्तार किया गया है। इनका संबंध बांग्लादेश में स्थित इस्लामिक आतंकवादी संगठन से है। पुलिस कमिश्नर महंता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन 'इमाम महमुदुर काफिला' (आईएमके) से जुड़े हुए है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की पहचान नसीमुद्दीन, जुनाब अली, अफराहीम हुसैन, मिजानुर रहमान, सुल्तान महमूद, मोहम्मद सिद्दीक अली, रशीदुल आलम, महिबुल खान, शाहरुख हुसैन, मोहम्मद दिलबर रज्जाक और जागीर मियां के रूप में हुई है।

केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार आईएमके का संबंध बांग्लादेश में स्थित इस्लामिक आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन से है। यह आतंकवादी संगठन भारत में प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएमके की स्थापना 2018 में ज्वेल महमूद उर्फ इमाम महमूद हबीबुल्लाह उर्फ सोहेल ने की थी। वह जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश का सदस्य रह चुका है। इमाम महमूद हबीबुल्लाह स्वयं को आईएमके का अमीर होने का दावा करता है और 'गजवा-ए- हिंद' की विचारधारा का प्रचार-प्रसार करता है। यह संगठन हिंसा के जरिए भारत में इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहता है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने बांग्लादेश की जेलों में बंद इस्लामिक आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों को रिहा कर दिया था।

बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर पूर्वोत्तर भारत में हिंसा के जरिए सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। इस उद्देश्य से दो बांग्लादेशी नागरिकों उमर और खालिद को असम में आतंकवादी गतिविधियों का विस्तार करने का जिम्मा दिया गया। इसके बाद इन दोनों आतंकवादियों ने असम के स्थानीय युवकों को अपने आतंकवादी संगठन में भर्ती किया। इन युवकों को गुप्त प्रशिक्षण शिविरों में बम चलाने और गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया।

इंकलाब (30 दिसंबर) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर असम को मुस्लिम बहुल राज्य में बदलने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय असम की 40 प्रतिशत जनसंख्या बांग्लादेशी मियां मुसलमानों की है। पाकिस्तान का प्रयास है कि इसमें 10 प्रतिशत की और वृद्धि की जाए। इस लक्ष्य से वह बांग्लादेशी मुसलमानों को त्रिपुरा और असम में घुसपैठ करवा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैंने राजनीति शुरू की तो असम में बांग्लादेशी मियां मुसलमानों की जनसंख्या 21 प्रतिशत थी, जो

2011 की जनगणना में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई और अब यह 40 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह जनसंख्या संतुलन को बदलकर इस क्षेत्र को अपना अंग बनाना चाहता है। हाल ही में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के एक नेता हसनत अबदुल्ला ने दावा किया है कि जल्द ही पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों को भारत से अलग कर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। वे गजवा-ए-हिंद के मंसूबे को कार्यान्वित करने के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारतीय राज्यों में घुसपैठ करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों को इन देश विरोधी गतिविधियों के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा उर्दू मीडिया की नजर में

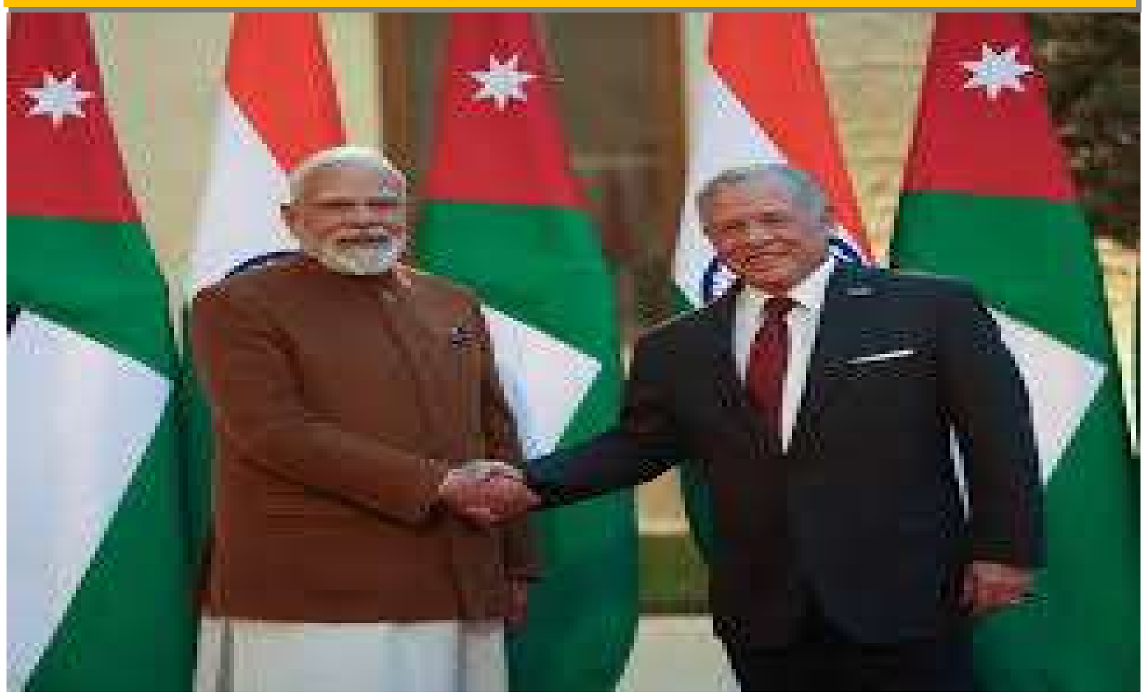

हिंदुस्तान (17 दिसंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जॉर्डन के अपने सरकारी दौरे के दौरान पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, डिजिटल समाधान और पेट्रा व एलोरा के बीच जुड़ाव से संबंधित समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत होगी। इससे पहले जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला द्वितीय ने अल-हुसैनिया पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने, क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार में वृद्धि, पूंजी निवेश, रक्षा व सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और कृषि समेत अन्य मुद्दों पर विचार किया गया।

पहुंचे। यह प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया का पहला दौरा था। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने मोदी को साइंस म्यूज्यिम और फ्रेंडशिप पार्क भी दिखाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। इथियोपिया एक महत्त्वपूर्ण अफ्रीकी देश है और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से अफ्रीका के साथ भारत के नए संबंधों की शुरुआत होगी।

समाचारपत्र के अनुसार भारत ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान स्थित अल-हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्थापित भारतीय-जॉर्डन सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्ठता केंद्र के लिए सहयोग देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि अगले पांच सालों में दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार पांच बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। मोदी ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि दोनों देशों को अपने पुराने व्यापारिक संबंधों को फिर से शुरू करने की जरूरत है। मोदी ने उन पुराने व्यापारिक रास्तों का भी उल्लेख किया जो गुजरात को पेट्रा के जरिए यूरोप से जोड़ते थे। गुजरात के भरूच बंदरगाह से अरब सागर के रास्ते जॉर्डन से व्यापार होता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के आपसी सहयोग से व्यापार और पर्यटन में भारी वृद्धि होगी।

उर्दू टाइम्स (18 दिसंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जॉर्डन के सफल दौरे के बाद इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा

हिंदुस्तान (19 दिसंबर) के अनुसार ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल-सईद ने मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया। मोदी ओमान के दो दिवसीय दौरे पर गए थे। दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक और पूंजी निवेश के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होगी। इससे दोनों देशों में विकास की गति तेज होगी और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत उनके कल्याण और विकास के लिए दृढ़संकल्प है। इस बैठक में ओमान में भारत द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों के 700 से अधिक छात्र भी शामिल हुए। ये स्कूल ओमान में 50 साल पहले स्थापित किए गए थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां भी हमारे लोगों को मदद की जरूरत होगी सरकार वहां मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत और ओमान

के बीच मांडवी से मस्कट तक सदियों पुराने रिश्ते हैं। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत ओमान को बुनियादी ढांचा, चिकित्सा और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान में भारत आज एशिया में सबसे आगे हैं। हाल ही में भारत चंद्रमा तक भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल है। इस अवसर पर उन्होंने ओमान के उद्योगपतियों की एक बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और ओमान के बीच 70 साल पुराने राजनयिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा, कृषि और समुद्री सहयोग से संबंधित छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

अजमेर दरगाह में प्रधानमंत्री द्वारा पेश की गई चादर

इंकलाब (23 दिसंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री की ओर से चादर लेकर अजमेर दरगाह पहुंचे और लाखों जायरीन (श्रद्धालु) की मौजूदगी में अजमेर शरीफ दरगाह में यह चादर चढ़ाई गई। दरगाह के सज्जादानशीन सैयद सलमान चिश्ती ने रिजिजू का स्वागत किया। दरगाह की परंपरा के मुताबिक रिजिजू की दस्तारबंदी (पगड़ी पहनाना) की गई। इस अवसर पर रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी का एक संदेश भी सुनाया। प्रधानमंत्री ने इस संदेश में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन

चिश्ती के 814वें उर्स पर सभी श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी और उनसे देश में शांति, भाईचारे और विकास के लिए दुआ करने का अनुरोध किया। इंकलाब के प्रतिनिधि ने सलमान चिश्ती से सवाल किया कि क्या किरेन रिजिजू अपनी ओर से या केंद्र सरकार की ओर से या फिर प्रधानमंत्री की ओर से चादर चढ़ाने के लिए दरगाह आए हैं? इस पर उन्होंने कहा कि यह चादर प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल की ओर से चढ़ाई गई है।

इससे पहले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके अदालत से अनुरोध किया था कि वह प्रधानमंत्री को यह निर्देश दे कि वे अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर न भेजें, क्योंकि इससे उनके द्वारा स्थानीय अदालत में दायर याचिका पर प्रभाव पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह भगवान श्री संकटमोचन महादेव विराजमान मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। यह मामला अदालत में लंबित है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को सूचीबद्ध नहीं करूंगा। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि कम से कम 26 दिसंबर तक इस याचिका को सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह चादर देश के विकास और जनता की भलाई के लिए चढ़ाई जाएगी। मैं अजमेर दरगाह राजनीति करने के लिए नहीं जा रहा हूं और न ही अदालत ने दरगाह में चादर चढ़ाने पर रोक लगाई है।

हमारा समाज (23 दिसंबर) ने दावा किया है कि अदालत में विचाराधीन याचिका के कारण अजमेर दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर के सिलसिले में प्रधानमंत्री आवास में किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया गया है और न ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमालुद्दीन सिद्दीकी के ही वहां पर जाने की कोई सूचना है। राज्य सरकार ने उर्स के मौके पर सख्त सुरक्षा प्रबंध किए थे। रिजिजू के साथ केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत और अजमेर दरगाह के दीवान के बेटे नसरुद्दीन चिश्ती भी मौके पर मौजूद थे। इस बार पाकिस्तान से श्रद्धालु नहीं आए हैं।

पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की नई पार्टी

उर्दू टाइम्स (23 दिसंबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। इसका नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने की घोषणा के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया था। मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर में नई पार्टी बनाने की घोषणा करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य जनता का विकास और जनकल्याण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पश्चिम बंगाल के लोग उनकी इस नई पार्टी में शामिल होंगे। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर कई दलों में रह चुके हैं। 2011 में वे कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। बाद में वे कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री बने। हुमायूं कबीर 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने मुर्शिदाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। 2021 में वे फिर से टीएमसी में शामिल हो गए और भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। हुमायूं कबीर ने घोषणा की कि वे मुर्शिदाबाद जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों बेलडांगा और रेजीनगर से चुनाव लड़ेंगे।

हमारा समाज (23 दिसंबर) के अनुसार हुमायूं कबीर ने चुनाव आयोग से 'मेज' का चुनाव चिन्ह मांगा है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर कोई भी दल उनके साथ गठबंधन करने के लिए सहमत नहीं होता है तो वे राज्य विधानसभा की सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की कि वे ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने और भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनकी पार्टी का समर्थन करें। संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद की आलोचना किए जाने का उल्लेख करते हुए कबीर ने कहा कि वे संघ प्रमुख का सम्मान करते हैं, लेकिन वे पश्चिम बंगाल के बारे में उनकी राय से सहमत नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का आरएसएस से गठजोड़ है। यही कारण है कि ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद राज्य में आरएसएस का वर्चस्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा अगले सप्ताह करेंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद का मूल निवासी हूं, इसलिए अपनी पार्टी का मुख्यालय मुर्शिदाबाद में ही स्थापित करूंगा।

बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता की हत्या से तनाव

चट्टान (20 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने वाले प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देशभर में भारत विरोधी उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही पूरे बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। गौरतलब है कि जब हादी मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकल रहा था तो कुछ नकाबपोश बंदूकधारियों ने उस पर गोलियां चलाई। हादी को घायलावस्था में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन जब उसकी हालत नाजुक हो गई तो बेहतर इलाज के लिए उसे एक विशेष एयर एंबुलेस से सिंगापुर भेजा गया। वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

उल्लेखनीय है कि शरीफ उस्मान हादी ने बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हादी की मौत की खबर मिलते ही पूरे बांग्लादेश में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने धानमंडी स्थित शेख मुजीबुर रहमान संग्राहलय पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश के दो बड़े अखबारों 'प्रोथोम आलो' और 'द डेली स्टार' के कार्यालयों पर हमला करके उनमें तोड़फोड़ की और आग लगा दी। 32 वर्षीय शरीफ उस्मान हादी कट्टरपंथी समूह 'इंकलाब मंच' का नेता था। उसे भारत के कट्टर आलोचकों में गिना जाता था। हादी ने एक मदरसे से आलिम की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उसने ढाका विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की थी। इन दिनों वह एक निजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्यरत था। शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान वह मीडिया में चर्चित हुआ था।

अवधनामा (21 दिसंबर) के अनुसार ढाका में हादी का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद देशभर में दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। हादी की शवयात्रा में भारत विरोधी नारे लगाए गए और कहा गया कि इस हमले के पीछे भारत की

प्रदर्शनकारियों ने ढाका में भारतीय उच्चायोग में घुसने का प्रयास किया। इसके जवाब में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश के कई नेताओं ने धमकी दी है कि देशद्रोही शेख हसीना को शरण देने वाले भारत को विखंडित कर दिया जाएगा और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को बांग्लादेश में मिलाकर 'ग्रेटर बांग्लादेश' का निर्माण किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रही है।

खुफिया एजेंसी 'रॉ' का हाथ है। इसी दौरान बांग्लादेश के शहर मैमनसिंह में उग्र मुसलमानों की भीड़ ने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को घेरकर मौत के घाट उतार दिया। जबकि लक्ष्मीपुर में बीएनपी के नेताओं के घरों में आग लगाई गई। हादी की नमाज-ए-जनाजा बांग्लादेशी संसद भवन के साउथ प्लाजा में अदा की गई। इसके बाद उसे ढाका विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कब्रिस्तान में बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया।

हिंदुस्तान (21 दिसंबर) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संगठन 'मीडिया फ्रीडम कोएलिशन' ने बांग्लादेश में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के कार्यालयों पर हमलों की निंदा की है। ढाका स्थित कई देशों के दूतावासों ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ बताया है।

एतेमाद (23 दिसंबर) के अनुसार कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले एक अन्य छात्र नेता मोतालेब सिकदर को गोली मारी है। नेशनल सिटीजन पार्टी की संयुक्त प्रधान समन्वयक महमूदा मितु ने बताया कि सिकदर को खुलना इलाके में गोली मारी गई थी। इसके बाद उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है।

उर्दू टाइम्स (18 दिसंबर) के अनुसार भारत सरकार ने बांग्लादेश स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों (आईवीएसी) के संचालन को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब करके प्रदर्शनकारियों द्वारा बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमले और देश में अल्पसंख्यकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना पर चिंता प्रकट थी।

औरंगाबाद टाइम्स (20 दिसंबर) के अनुसार भारत स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने भी अपना वीजा सेक्शन अस्थाई रूप से बंद कर दिया है।

औरंगाबाद टाइम्स (27 दिसंबर) के अनुसार भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले की तीन हजार घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में हत्या, लूटपाट, आगजनी और भूमि पर जबरन कब्जा शामिल हैं।

एतेमाद (27 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में नेपाल में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया।

उर्दू टाइम्स (22 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने ढाका विश्वविद्यालय के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर 'शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल' कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय में लगी मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को भी आग के हवाले कर दिया है।

एतेमाद (29 दिसंबर) के अनुसार ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त एसएन मोहम्मद नजरूल इस्लाम ने आरोप लगाया है कि उस्मान हादी की हत्या के दो आरोपी बांग्लादेश से भागकर भारत चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दो संदिग्ध हमलावर फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख मैमनसिंह के हालुआघाट सीमा से भारत में घुसे। इसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर सामी ने दोनों को मेघालय के शहर तुरा पहुंचा दिया। अभी ये लोग वहीं पर रह रहे हैं। नजरूल इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश सरकार इन संदिग्ध हमलावरों की वापसी के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रही है। दूसरी ओर, भारत सरकार ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मेघालय में प्रवेश नहीं किया है।

औरंगाबाद टाइम्स (31 दिसंबर) ने दावा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में एक अतिवादी संगठन नेशनल आर्म्ड रिजर्व (एनएआर) का गठन करने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने और देश की सुरक्षा तंत्र को प्रभावित करने के लक्ष्य से बांग्लादेश के लगभग नौ हजार कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं को एनएआर में शामिल करने की योजना है। आईएसआई बांग्लादेश को पूरी तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाना चाहती है। इस अतिवादी संगठन की निगरानी के लिए बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख गुलाम आजम के बेटे सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी को चुना गया है।

हमारा समाज (25 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते संबंधों पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि बांग्लादेश में नफरत की जो ज्वाला भड़काई जा रही है वह सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका प्रभाव दक्षिण एशिया के अनेक देशों पर पड़ेगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत की कुछ ताकतें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है।

हमारा समाज (19 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने दोनों

देशों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इसका समाधान निकालने के लिए कोई कारगर कदम उठाएं।

सियासत (20 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बांग्लादेश के घटनाक्रम का लाभ उठाकर भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत की भावना भड़काई जा रही है। समाचारपत्र ने दोनों देशों की सरकारों से अपील की है कि वे अपने-अपने देश में अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराएं।

पाकिस्तान से रक्षा समझौते के बाद लीबिया के सेना प्रमुख की मौत

हिंदुस्तान (28 दिसंबर) के अनुसार पिछले दिनों पाकिस्तान और लीबिया के बीच चार बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के कुछ ही दिनों के बाद लीबिया के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने लीबिया का दौरा किया था। उन्होंने लीबिया की नेशनल आर्मी के साथ चार बिलियन डॉलर मूल्य के हथियार बेचने का समझौता किया था। समाचारपत्र के अनुसार मुनीर ने लीबिया के पूर्वी हिस्से के शक्तिशाली सैन्य नेता फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार और उनके बेटे लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम हफ्तार के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह समझौता किया था। इस समझौते में तय हुआ था कि पाकिस्तान लीबिया को सैन्य विमान, टैंक, तोपें और भारी मात्रा में गोला बारूद उपलब्ध कराएगा।

उल्लेखनीय है कि इन दिनों पाकिस्तान में आर्थिक संकट व्याप्त है। इसे टालने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने लीबिया की नेशनल आर्मी के साथ यह समझौता किया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पाकिस्तान के साथ हुआ यह समझौता लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में लीबिया पर सैन्य उपकरण खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उल्लेखनीय है कि इस समय लीबिया में दो समानांतर सरकारें चल रही हैं। पूर्वी लीबिया पर नेशनल आर्मी का कब्जा है। इसके प्रमुख फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार हैं। हफ्तार को लीबिया की प्रतिनिधि सभा का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक नेशनल आर्मी को मान्यता नहीं दी है। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबेह हैं। इस सरकार का मुख्यालय त्रिपोली है। समाचारपत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं यह समझौता उसका खुला उल्लंघन है।

एतेमाद (25 दिसंबर) के अनुसार लीबिया के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद समेत आठ लोगों की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। यह दुर्घटना तुर्किये की

राजधानी अंकारा के नजदीक हुई है। तुर्किये के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' को बताया कि तुर्किये सरकार की सर्च टीमें दुर्घटनाग्रस्त विमान के अवशेषों को खोजने का प्रयास कर रही हैं। लीबिया के सैन्य उच्च कमान का यह प्रतिनिधिमंडल तुर्किये के साथ सैन्य समझौते के बारे में बातचीत करने के बाद वापस स्वदेश लौट रहा था। तुर्किये के गृह मंत्री ने घटनास्थल पर संवाददाताओं को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा तीन किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण दुर्गम है, इसलिए अवशेषों को खोजने में परेशानी हो रही है।

लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबेह ने इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह लीबिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने लीबिया के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की। एर्दोगान ने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। एर्दोगान ने कहा कि इस दुर्घटना के पीछे किसी साजिश की संभावना नहीं है, बल्कि यह दुर्घटना तकनीकी कारणों से हुई है। लीबिया सरकार ने तीन दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है।

समाचारपत्र के अनुसार 2011 में सैन्य विद्रोह के दौरान लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी गई थी। तब से लीबिया गृहयुद्ध का शिकार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में तुर्किये सेना लीबिया में तैनात है। इस सरकार के अधिकार क्षेत्र में त्रिपोली और उसके आसपास के इलाके हैं। 2020 में दोनों देशों के बीच हुए सैन्य समझौते के बाद तुर्किये की सेना लीबिया भेजी गई थी। जबकि लीबिया के अन्य भागों पर सेना के विभिन्न गुटों ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जिस नेशनल आर्मी के साथ सैन्य समझौता किया है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ■

इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा

उर्दू टाइम्स (21 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 केस में 17-17 साल की कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया। यह मामला मई 2021 में सऊदी अरब दौरे के दौरान इमरान खान को उपहार में दिए गए महंगे ज्वेलरी सेट से जुड़ा है। यह ज्वेलरी सेट सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को उपहार स्वरूप दिए थे। आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने सरकारी तोशाखाना से बहुत ही कम कीमत पर इस बेशकीमती ज्वेलरी सेट को खरीद लिया। एफआईए ने आरोप लगाया था कि तोहफों की खरीद-फरोख्त में नियमों का उल्लंघन किया गया और देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया।

अदालत ने इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम के तहत सात साल की सजा सुनाई है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं में 17 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इन दोनों पर एक करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर इन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दूसरी ओर, इमरान खान के वकील ने अदालत में तर्क दिया था कि इस उपहार को खरीदने में निर्धारित सरकारी नियमों का पालन किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण इमरान खान और उनकी पत्नी को झूठे आरोपों में फंसाकर सजा देना चाहती है।

गौरतलब है कि इमरान खान अलग-अलग मामलों में करीब ढ़ाई साल से जेल में बंद हैं। पाकिस्तान के वर्तमान सैन्य तानाशाह आसिम मुनीर से इमरान खान का टकराव जगजाहिर है। इस मामले में आसिम मुनीर को नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) और बिलावल भुट्टों की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का समर्थन प्राप्त है।

चट्टान (21 दिसंबर) के अनुसार 73 वर्षीय इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इमरान खान और उनकी पत्नी को सुनाई गई सजा की निंदा की है। पीटीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आसिम मुनीर के इशारे पर एक कठपुतली अदालत ने जेल के अंदर बंद कमरे में यह फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई निष्पक्ष रूप से नहीं हुई है। पीटीआई के इस बयान को खारिज करते हुए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि अदालत ने निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के यह फैसला सुनाया है। तरार ने आरोप लगाया कि इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के एक असंतुष्ट गुट की मदद से चुनावों में धांधली करके सत्ता पर कब्जा किया था।

पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट के हमलों में वृद्धि

हिंदुस्तान (28 दिसंबर) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने 25 दिसंबर को बलूचिस्तान के ओरमाड़ा और सुराब में दो अलग-अलग हमलों में छह पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। एक अन्य बलूच संगठन बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के प्रवक्ता दोस्तैन बलोच ने पुष्टि की है कि उनके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कच्छी जिले के धादर इलाके में एक पुलिस कैंप पर हमला किया। इस हमले में कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। उन्होंने कहा कि हमलों का यह सिलसिला जारी रहेगा।

उर्दू टाइम्स (23 दिसंबर) के अनुसार पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की दो अलग-अलग कार्रवाई में नौ आतंकवादी मारे गए हैं। इन आतंकवादियों का संबंध प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से बताया जाता है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (20 दिसंबर) के अनुसार टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के बोया इलाके में स्थित एक सैन्य शिविर पर हमला किया। एक आत्मघाती हमलावर ने बारूद से भरी एक कार को कैंप की दीवार से टकरा दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद पांच सशस्त्र हमलावरों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी में तीन आतंकवादी मौके पर मारे गए। जबकि चार सुरक्षाकर्मी भी मारे गए।

चट्टान (24 दिसंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में आतंकवादियों ने एक पुलिस वैन पर हमला करके पांच पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को उचित मुआवजा देगी।

चट्टान (27 दिसंबर) के अनुसार आतंकवाद निरोधक पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 1588 आतंकवादी घटनाएं हुईं। इनमें 54 ड्रोन हमले भी शामिल हैं। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि इन हमलों का संचालन अफगानिस्तान से किया जा रहा है। सबसे ज्यादा 391 घटनाएं बन्नू इलाके में दर्ज की गईं। जबकि उत्तरी वजीरिस्तान में 181 घटनाएं दर्ज की गईं। बन्नू में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में 27 पुलिसकर्मी मारे गए। जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 53 आतंकवादी मारे गए। पेशावर में 163 आतंकवादी घटनाएं हुईं। डेरा इस्माइल खान में 152 और खैबर में 119 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गईं।

डेनमार्क के शिक्षण संस्थानों में बुर्का पर प्रतिबंध का फैसला

उर्दू टाइम्स (25 दिसंबर) के अनुसार डेनमार्क सरकार ने देश के सभी स्कूलों व कॉलेजों में बुर्का और नकाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि डेनमार्क में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब पहनने पर पहले से ही पाबंदी है। डेनमार्क के मंत्री रासमस स्टोक्लुंड ने कहा कि देश के शिक्षण संस्थानों में बुर्का, नकाब या चेहरा ढकने वाला कोई भी पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि डेनमार्क सरकार ने 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, हिजाब और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की भी व्यवस्था है। अब सरकार इसका विस्तार शिक्षण संस्थानों तक भी करना चाहती है। इस संबंध में फरवरी 2026 में डेनमार्क की संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

मानवाधिकार संगठनों और मुस्लिम समूहों ने डेनमार्क सरकार के इस फैसला का विरोध किया है। उन्होंने सरकार के इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जबकि सरकार समर्थकों का कहना है कि इससे प्रवासी पृष्ठभूमि वाले मुसलमानों को डेनमार्क के समाज में घुलने-मिलने में मदद मिलेगी। इससे पहले ऑस्ट्रिया की संसद ने एक कानून पारित करके 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

दूसरी ओर, डेनमार्क सरकार के इस फैसले का आगरा के मुसलमानों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि डेनमार्क सरकार का यह फैसला मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। एक मुस्लिम युवक नदीम नूर ने कहा कि डेनमार्क एक अलग देश है और वे भारत के नागरिक हैं। भारतीय संविधान में मुसलमानों को अपने धार्मिक आस्था के अनुसार जीवन गुजारने की पूरी स्वतंत्रता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद शरीफ कुरैशी ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के लिए पर्दा करना अनिवार्य है, इसलिए मुस्लिम महिलाएं नकाब और बुर्का पहनती हैं।

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बढ़ता टकराव

एतेमाद (31 दिसंबर) के अनुसार यमन में कुछ क्षेत्रों के कब्जे को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में ठन गई है। सऊदी अरब ने यूएई से हथियारों की खेप आने के बाद दक्षिण यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर बमबारी की। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि वह यूएई की इन हरकतों को बेहद खतरनाक समझता है, क्योंकि वह यमन के दक्षिणी इलाकों पर कब्जा करने वाले विद्रोही संगठन दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (एसटीसी) को सैन्य सहायता उपलब्ध करा रहा है। सऊदी अरब की चेतावनी के बावजूद एसटीसी ने घोषणा की है कि हम यूएई के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखेंगे। जबकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने चेतावनी दी है कि अगर यूएई की सेना यमन को 24 घंटे के अंदर खाली नहीं करती तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वहीं, यूएई ने सऊदी अरब से अपील की है कि वह इस क्षेत्र में युद्ध को बढ़ावा न दे और समझदारी से काम ले।

इस घटनाक्रम के बाद यमन में युद्ध का एक नया फ्रंट खुल गया है। गौरतलब है कि यमन में पिछले एक दशक से हूती विद्रोहियों और यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद (पीएलसी) के बीच युद्ध जारी है। पीएलसी ने अपना मुख्यालय सऊदी अरब में स्थापित कर रखा है। वहीं से वह सऊदी सेना की सहायता से हूतियों के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूएई का फैसला अरब एकजुटता गठबंधन के नियमों के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि यमन के उत्तरी हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। जबकि दक्षिणी हिस्से पर नियंत्रण को लेकर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन और यूएई समर्थित एसटीसी के बीच भीषण जंग छिड़ गई है।

पाकिस्तानी अखबार **जंग** के अनुसार यमन और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहा है। यमन में जो कबीले आबाद हैं उनका संबंध सऊदी अरब के कबीलों से है। वहीं, हूती पिछले 1500 सालों से यमन में

सऊदी अरब की सहायता करता है तो यूएई से उसके संबंध बिगड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वहां से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। पाकिस्तान का प्रयास है कि अमेरिका की मध्यस्थता से सऊदी अरब और यूएई में समझौता करवाया जाए। हालांकि, वह अभी तक इसमें सफल नहीं हुआ है।

रह रहे हैं। हूतियों का संबंध इस्लाम के शिया संप्रदाय से है। यही कारण है कि लंबे समय से सऊदी अरब समर्थित सुन्नी कबीलों से उनका संघर्ष जारी है। जबकि शिया देश ईरान और हूतियों के बीच लंबे समय से संबंध रहा है। ईरान हूतियों को पिछले एक दशक से भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध करा रहा है। 2014 में यमन में गृहयुद्ध छिड़ने के कारण यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार (पीएलसी) को यमन छोड़कर सऊदी अरब भागना पड़ा था। समाचारपत्र के अनुसार वर्तमान में यमन चार भागों में बंटा हुआ है। एक भाग पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। जबकि दूसरे भाग पर सऊदी अरब समर्थक सरकार (पीएलसी) का नियंत्रण है। तीसरे भाग पर संयुक्त अरब अमीरात समर्थक एसटीसी ने कब्जा कर रखा है। जबकि चौथे भाग पर स्थानीय कबीलों का कब्जा है।

यमन के घटनाक्रम से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को हो रही है, क्योंकि उसका सऊदी अरब और यूएई दोनों से निकटवर्ती संबंध है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का रक्षा समझौता है। इस समझौते के तहत अगर कोई भी देश सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर हमलावर देश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर, यूएई में लगभग 20 लाख पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। अगर पाकिस्तान

एतेमाद (31 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब समर्थित पीएलसी के अध्यक्ष और यमन के राष्ट्रपति रशाद अल-अलीमी ने यूएई को आदेश दिया है कि वह यमन से अपने सैनिकों को फौरन वापस बुला ले। इस तरह से उन्होंने यमन और यूएई के बीच के रक्षा समझौते को खत्म कर दिया है। अल-अलीमी ने पूरे देश में 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (31 दिसंबर) के अनुसार पीएलसी के अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी ने यूएई के साथ हुए रक्षा समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। अल-अलीमी ने कहा कि सरकार ने यह फैसला किया है कि यमन के सभी बंदरगाहों और रास्तों पर नाकेबंदी की जाए ताकि यूएई समर्थित एसटीसी को युद्ध से रोका जा सके। उन्होंने पुष्टि की है कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने तीन बार एसटीसी के ठिकानों पर हमले किए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हमारे मुस्लिम भाई यूएई की ओर से यमन में जो आक्रामक कार्रवाई की जा रही है वह बेहद खतरनाक है। इसके कारण इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है और एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है।

पृष्ठभूमिः यूएई समर्थित एसटीसी ने पिछले सप्ताह यमन के दक्षिण-पूर्वी इलाके में कई महत्त्वपूर्ण शहरों और तेल भंडारों पर फिर से

कब्जा कर लिया है। पहले ये क्षेत्र सऊदी समर्थित सेनाओं के नियंत्रण में थे। 2022 में हुए युद्धविराम समझौते के बाद सऊदी समर्थित सेनाओं ने इस क्षेत्र को खाली कर दिया था। यमन के घटनाक्रम को सऊदी अरब और यूएई का मीडिया अपने-अपने ढंग से पेश कर रहा है। यूएई समर्थित 'स्काई न्यूज अरबिया' ने एसटीसी के नेता मंसूर सालेह का इंटरव्यू प्रसारित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए एसटीसी ने शांति स्थापित करने के लिए कार्रवाई की है। कतर के 'अल जजीरा टीवी' ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि यमन सरकार के सदस्य हद्रामौत और अल-महराह प्रांतों में एसटीसी के सैन्य विस्तार के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए सऊदी अरब गए हैं।

दूसरी ओर, सऊदी समर्थित अल अरबिया न्यूज ने अपनी कवरेज में कहा है कि सऊदी अरब समर्थित पीएलसी के नेता रशाद अल-अलीमी ने एसटीसी की हाल की एकतरफा कार्रवाइयों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों से यमन की कानूनी हैसियत और सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचता है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यमन के घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि भौगोलिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में यूएई और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। खाड़ी के इन दोनों देशों के बीच ओपेक में किए गए फैसलों, सूडान, यमन और अन्य कई मामलों में गंभीर मतभेद हैं। यूएई ने सऊदी अरब के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए जो रुख अपनाया है उसके पीछे अमेरिका का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका सऊदी अरब में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव से परेशान है। हाल ही में तेल उत्पादक देशों के संगठन 'ओपेक' ने तेल के उत्पादन में कटौती करने का जो फैसला किया था उससे यूएई सहमत नहीं है। यूएई ने धमकी दी है कि वह ओपेक से अपना संबंध तोड़ लेगा। यूएई और सऊदी अरब के बीच विवाद का एक और कारण यूएई द्वारा 'यासात' के इलाके को 'समुद्री संरक्षित क्षेत्र' घोषित करना है। सऊदी अरब ने यूएई के इस फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है।

इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने पर विवाद

कौमी तंजीम (27 दिसंबर) के अनुसार इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने से एक नया विवाद शुरू हो गया है। अरब देशों ने इजरायल के इस फैसले का विरोध किया है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई एक वीडियो कॉल का फुटेज जारी किया गया है। इसमें नेतन्याहू को मान्यता के आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। गौरतलब है कि

सोमालीलैंड और उसकी राजधानी हरगेइसा सोमालिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल एक लाख 75 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं दक्षिण-पश्चिम में इथियोपिया, उत्तर-पश्चिम में जिबूती, उत्तर में अदन की खाड़ी और पूर्व में सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र से लगती है। इस देश की समुद्री तटरेखा 740 किलोमीटर लंबी है।

1991 में गृहयुद्ध के कारण विद्रोहियों ने सोमालिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद सियाद बर्रे को अपदस्थ कर दिया था। इसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे सोमालिया में अशांति पैदा हो गई। इसका लाभ उठाकर सोमालीलैंड ने सोमालिया से अलग होने की घोषणा कर दी और अब्दिरहमान अहमद अली तूर सोमालीलैंड के राष्ट्रपति बने। सोमालीलैंड की सरकार ने अगस्त 2000 में संविधान का प्रारूप पेश किया। इसमें सोमालिया से अलग होने की पुष्टि की गई थी। 2001 में इस क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें लोगों ने सोमालीलैंड के पक्ष में वोट दिया। सोमालीलैंड की अपनी सरकार, सेना और पुलिस व्यवस्था है। इसके बावजूद अभी तक किसी भी विदेशी सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी थी। सोमालीलैंड में 2024 में हुए चुनाव में अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही राष्ट्रपति चुने गए। सोमालीलैंड की जनसंख्या लगभग 62 लाख है। इसमें तीन कबीले हैं। इनमें से 'इसाक' कबीला सबसे बड़ा है और देश की राजनीति में इसी कबीले का वर्चस्व है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 'दिर' कबीला और पूर्वी क्षेत्र में 'दारोद' कबीले के लोग रहते हैं। सोमालीलैंड में सोमाली, अरबी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है।

समाचारपत्र का कहना है कि सोमालीलैंड सोमालिया की तुलना में अधिक स्थिर देश है। सोमालिया कहने को तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसे पूरी तरह से विकसित लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। सोमालिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े अल-शबाब का वर्चस्व है। सोमालीलैंड में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यह सोमालिया की तुलना में ज्यादा विकसित है। इसकी एक संसद है, जिसमें दो सदन हैं। दोनों सदनों में 82-82 सदस्य हैं। सोमालीलैंड पहले ब्रिटिश उपनिवेश था और 1960 में ब्रिटेन से आजाद हुआ। फिर यह इटली

के कब्जे वाले सोमालिया के साथ मिलकर सोमाली गणराज्य का हिस्सा बना। 1991 में सोमालिया में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई, जिसका लाभ उठाकर सोमालीलैंड ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।

कौमी तंजीम (29 दिसंबर) के अनुसार इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) और 21 मुस्लिम देशों ने एक साझा बयान में इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने पर चिंता प्रकट की है। इन देशों ने इजरायल से मांग की है कि वह सोमालीलैंड की मान्यता को फौरन रद्द करे। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया, कोमोरोसो, जिबूती, गाम्बिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सोमालिया, सूडान, तुर्किये, ओमान और यमन शामिल हैं। इस बयान में कहा गया है कि इस फैसले का अफ्रीका और लाल सागर के क्षेत्र की शांति व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। बयान में यह भी आरोप लगाया है कि इजरायल ने अंतरराष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। इसका लक्ष्य फिलिस्तीनी जनता को उनकी भूमि से बेदखल करना है। इन देशों ने चिंता प्रकट की है कि इजरायल फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर सोमालीलैंड में बसा सकता है।

यूरोपीय यूनियन ने इजरायल के इस फैसले को सोमालिया के संविधान, संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। इसके अतिरिक्त मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब लीग का एक आपातकालीन अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने से पैदा होने वाले संकट पर विचार किया गया। सोमालिया के सूचना मंत्री दाउद इवेइस जामा ने सऊदी मीडिया नेटवर्क 'अल अरबिया' को बताया कि इजरायल का यह फैसला लोकतांत्रिक सोमालिया की संप्रभुता पर करारा हमला है। उन्होंने अमेरिका के इस बयान का स्वागत किया, जिसमें उसने कहा था कि वह इजरायल के इस फैसले से सहमत नहीं है।

हिंदुस्तान (29 दिसंबर) के अनुसार सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने सोमालियाई संसद के एक विशेष अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि इजरायल का यह फैसला सोमालिया की संप्रभुता और अखंडता पर करारा हमला है। उन्होंने कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है। महमूद ने कहा कि इजरायल के इस फैसले से अलगाववादी आंदोलनों को प्रोत्साहन मिलेगा और विश्व के अनेक भागों में शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सोमालिया फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से बेदखल करने के फैसले को स्वीकार नहीं करेगा और न ही वह अपनी भूमि पर किसी भी विदेशी अड्डे की स्थापना को स्वीकार करेगा।

औरंगाबाद टाइम्स (28 दिसंबर) के अनुसार सोमालिया के विदेश राज्य मंत्री अली मोहम्मद उमर ने इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने को सोमालिया पर हमला करार दिया है। उन्होंने

अड्डा स्थापित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इजरायल का यह फैसला अरब देशों के लिए खतरा है, इसलिए सभी अरब देशों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए।

एतेमाद (30 दिसंबर) के अनुसार यमन के हूती समूह ने इजरायल और सोमालीलैंड के बीच बढ़ती दोस्ती पर चिंता प्रकट करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने अपना फैसला नहीं बदला तो हूती विद्रोही उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे। तुर्किये के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद दावुतोग्लू ने कहा है कि इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देना इस्लाम के लिए खतरे की घंटी है। इजरायल मुस्लिम देशों की एकता को तोड़ना चाहता है और इस बहाने वह अदन की खाड़ी तक पहुंचना चाहता है। उसका लक्ष्य मिस्र और सऊदी अरब को अपने घेरे में लेना है।

इजरायल से मांग की कि वह अपने फैसले को फौरन वापस ले। दूसरी ओर, सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने बिना फिलिस्तीन का नाम लिए कहा कि वे किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं और न ही वे क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालना चाहते हैं। इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने के बाद पूरे सोमालीलैंड में जश्न मनाया जा रहा है।

हिंदुस्तान (31 दिसंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में सोमालिया के प्रतिनिधि अबुकर दाहिर उस्मान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वह इजरायल द्वारा सोमालीलैंड की मान्यता को रद्द करने के लिए इजरायल पर दबाव डाले। उन्होंने कहा कि इजरायल का यह फैसला अफ्रीका और लाल सागर की शांति को तबाह कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में सोमालिया के विघटन को सहन नहीं करेंगे और इसका डटकर मुकाबला करेंगे।

हिंदुस्तान (30 दिसंबर) के अनुसार सोमालिया के सूचना मंत्री दाउद इवेइस ने आरोप लगाया है कि इजरायल सोमालीलैंड में अपना सैन्य

एतेमाद (28 दिसंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे फिलहाल किसी ऐसी योजना का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि क्या किसी को पता है कि सोमालीलैंड क्या है? दूसरी ओर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल सोमालीलैंड के साथ कृषि, स्वास्थ्य, तकनीक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग करेगा। उन्होंने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति को इजरायल आने का निमंत्रण भी दिया है।

उर्दू टाइम्स (28 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने का फैसला बेहद खतरनाक भू-रणनीतिक योजना का हिस्सा है। इसका प्रभाव अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व और पूरे इस्लामिक जगत में होगा। यह कदम ऐसे वक्त में

उठाया गया है जब गाजा का भविष्य अनिश्चित है। यही कारण है कि इजरायल के इस फैसले ने दुनियाभर के मुस्लिम देशों को बेचैनी और खतरे में डाल दिया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक प्रतिक्रिया फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय की है। उसने इजरायल के इस फैसले को अरब जगत और इस्लाम के लिए खतरा बताया है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने संदेह व्यक्त किया है कि इजरायल इस बहाने गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करके फिलिस्तीन समस्या को हमेशा के लिए दफन करना चाहता है। इजरायल का यह फैसला पूरे विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। सभी देशों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए।

इजरायल द्वारा ईरान पर दोबारा हमले की चेतावनी

उर्दू टाइम्स (23 दिसंबर) के अनुसार इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि इजरायली सेना अपने दुश्मनों के खिलाफ किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद युद्ध का विस्तार होता गया। इस युद्ध में ईरान और यमन सहित कई देश शामिल होते चले गए। ऐसी स्थिति में इजरायल जब और जहां जरूरी समझेगा दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि वह इजरायल के खिलाफ सक्रिय तत्वों को आर्थिक और सैन्य सहायता लगातार उपलब्ध करवा रहा है। इजरायल को नुकसान पहुंचाने वाले हर मंसूबे के पीछे ईरान का हाथ है। इजरायल अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह किसी भी दुश्मन पर हमला करके उसे तबाह कर सकता है।

इससे पहले अमेरिकी मीडिया में यह दावा किया गया था कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प से वाशिंगटन में मुलाकात के दौरान ईरान पर नए हमले के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद इजरायली सेना प्रमुख का यह बयान आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल इस बात से चिंतित है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में विस्तार कर रहा है। दूसरी ओर, ईरान ने भी इजरायल के नए हमलों पर चिंता जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान पर एक और हमले की संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूसी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर युद्ध थोपा गया तो वह इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने दावा किया कि हम हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं।

हिंदुस्तान (25 दिसंबर) के अनुसार इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि इजरायल गाजा को कभी भी पूरी तरह से

खाली नहीं करेगा और फिलिस्तीनी इलाके के अंदर एक सैन्य ईकाई बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना पूरे गाजा में तैनात रहेगी। हम गाजा के अंदर तक हैं और हम इसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम उत्तरी गाजा में एक इजरायली इन्फैंट्री ब्रिगेड की चौकियां स्थापित करेंगे। इसका उद्देश्य इजरायल की रक्षा करना होगा।

एतेमाद (25 दिसंबर) के अनुसार हमास के एक उच्चाधिकारी ओसामा हमदान ने कहा है कि हम गाजा में विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने इजरायल पर आरोप लगाया कि वह बार-बार युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इजरायल युद्धविराम के दूसरे चरण को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम नि:शस्त्रीकरण की योजना को कार्यान्वित नहीं करेंगे और फिलिस्तीनियों के आंतरिक मामलों में इजरायली हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे।

सियासत (22 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि इजरायल एक और युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इजरायल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बहाने ईरान को एक बार फिर से निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका इसका परोक्ष रूप से समर्थन कर रहा है। इजरायल का इरादा फिलिस्तीन को खाली करने का नहीं है। यही कारण है कि इजरायल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की है कि इजरायली सेना गाजा को खाली नहीं करेगी। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और दुनिया के दूसरे देशों की जिम्मेवारी बनती है कि वे नेतन्याहू को फिर से युद्ध की ज्वाला भड़काने से रोकें। अपनी रक्षा करने के लिए दुनिया के हर देश को हथियार बनाने का पूरा अधिकार है। इतिहास गवाह है कि ईरान कभी भी अमेरिका या पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आया है। यही कारण है कि इजरायल गाजा में तबाही मचाने के बाद अब ईरान को फिर से अपना निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है।

आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी हमले

चट्टान (27 दिसंबर) के अनुसार अमेरिकी सेना ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर जबर्दस्त हमले किए हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी थी कि अगर इस्लामिक आतंकवादी नाइजीरिया के ईसाइयों पर हमले करेंगे तो उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की पुष्टि की है। जबकि ट्रम्प ने कहा कि ये हमले क्रिसमस की रात को किए गए थे। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि मैंने इन आतंकवादियों को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों की हत्या का सिलसिला बंद नहीं किया तो उन्हें जहन्नुम में भेज दिया जाएगा और अब हमने उन्हें जहन्नुम में भेज दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमले नाइजीरिया सरकार के सहयोग से किए गए हैं। अमेरिका ने नाइजीरियाई नागरिकों को वीजा जारी

करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और नाइजीरिया को मिलने वाली अमेरिकी सहायता में भी भारी कटौती की गई है। गौरतलब है कि नाइजीरिया में पिछले 15 सालों से गृहयुद्ध जारी है। नाइजीरिया में आईएसआईएस से जुड़े बोको हराम के आतंकवादी अब तक 40 हजार लोगों की हत्या कर चुके हैं और 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं।

एतेमाद (21 दिसंबर) के अनुसार अमेरिका ने सीरिया में भी आईएसआईएस के अड्डों पर हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया है कि आईएसआईएस ने सीरिया में तीन अमेरिकी नागरिकों की हत्या कर दी थी, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक आईएसआईएस का खात्मा नहीं हो जाता तब तक सीरिया का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने स्पष्ट किया है कि ये हमले किसी युद्ध की शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि निर्दोष अमेरिकी नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए थे। इन हमलों आईएसआईएस के कैंपों और हथियारों के भंडारों को निशाना बनाया गया है।

एतेमाद (27 दिसंबर) के अनुसार सीरिया के शिया बहुल शहर होम्स की एक मस्जिद में हुए धमाके में पांच लोग मारे गए और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस हमले के पीछे आतंकवादियों का हाथ है।

औरंगाबाद टाइम्स (31 दिसंबर) के अनुसार तुर्किये के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में आईएसआईएस के आतंकवादियों द्वारा सेना पर हमले के बाद पूरे देश में आईएसआईएस समर्थकों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। तुर्किये के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने दावा किया है कि सेना ने देश के 21 प्रदेशों में एक साथ छापे मारकर 357 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध आईएसआईएस से है। इससे पहले क्रिसमस के मौके पर 100 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख को सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान

एतेमाद (23 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों को नई दिशा देने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'किंग अब्दुल्लअजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस' से सम्मानित किया है। इस संबंध में हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में भाग लेने के लिए आसिम मुनीर सऊदी अरब आए थे। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई दिशा देने और सैन्य मामलों में एक दूसरे को सहयोग देने पर विचार किया गया।

उर्दू टाइम्स (20 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने भीख मांगने के आरोप में

इस वर्ष 24 हजार पाकिस्तानियों को देश से निष्कासित किया है। पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी के प्रमुख रिफत मुख्तार राजा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने अपने देश से जिन पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित किया है वे मक्का और मदीना समेत कई शहरों में भीख मांग रहे थे। इन लोगों ने उमरा व टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल किया था। रिफत मुख्तार ने कहा कि सऊदी अरब के साथ-साथ यूएई ने भी पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस साल यूएई से छह हजार पाकिस्तानी भिखारियों को निष्कासित किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने अरब देशों में जाने वाले भिखारियों को रोकने हेतु सख्त कदम उठाए हैं। पिछले दो सालों में डेढ़ लाख संदिग्ध लोगों को हवाई अड्डों पर अरब देशों में जाने से रोका गया है। इसके अतिरिक्त अजरबैजान ने भी ढाई हजार पाकिस्तानी भिखारियों को अपने देश से निकाला है। उन्होंने कहा कि जो लोग भीख मांगने के आरोप में विदेशों से निष्कासित किए गए हैं उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

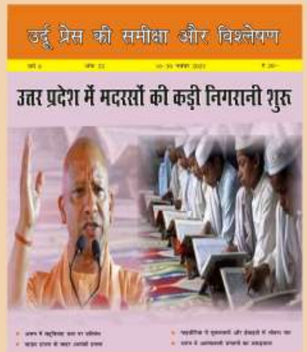

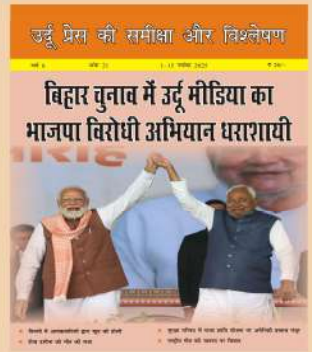

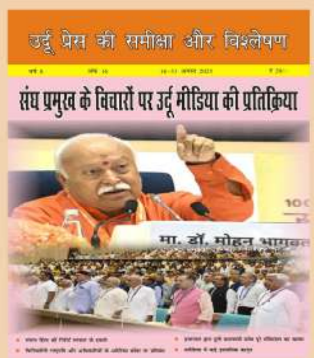

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in